प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 45 | मूल्य 15 रुपये | 30 मार्च-05 अप्रैल, 2025

100 ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी 32वें स्थान पर

मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने फिर छुड़ाए 'पसीने'

मंत्रिमंडल विस्तार की 'गुड न्यूज' लेकर चारधाम यात्रा के बंदोबस्त में जुटे सीएम धामी

वर्ष 14 | अंक 45

दिव्य हिमगिरि

30 मार्च-05 अप्रैल, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

पत्रकारों की कलम पर सख्ती क्यूँ?

एक लोकतांत्रिक देश के संघीय ढांचे की अहम पहचान है सवाल पूछना और अभिव्यक्ति की आजादी। नागरिकों की आवाज को समाचार में जगह देना पत्रकार का दायित्व होता है। अगर वह सच्चाई सामने नहीं लाएगा, जनता की परेशानियों तथा उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखेगा, तो पत्रकारिता अपना मूल उद्देश्य खो देगी। लेकिन आलम यह है कि शासन तंत्र अपने खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुनना चाहता। इसकी बानगी गुवाहाटी में देखने को मिली, जहां एक सहकारी बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में एक अदालत ने पत्रकार को जमानत दे दी। उस बैंक में अहम पदों पर सत्ता से जुड़े रसूखदार लोग काबिज हैं और वह पत्रकार वहां चल रही अनियमितताओं को लेकर लगातार अपने समाचार पोर्टल पर लिख रहा था। हालांकि इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उस पत्रकार ने जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां की थी। व्यवस्था के विरोध में जनता के लिए लिखने वाले पत्रकारों के प्रति शासन की असहिष्णुता की खबरें अक्सर सामने आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई पत्रकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा। तमाम वैश्विक एजेंसियां भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रही हैं। यह खेदजनक है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लगातार नीचे खिसक रहा है। 180 देशों में भारत वर्तमान में 159वें स्थान पर है। वर्ष 2003 से ही भारत का प्रदर्शन खराब आंका जा रहा है। सूचकांक के अनुसार, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये और रूस के बराबर माना जा रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भारत की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि चीन और रूस निचले पायदान पर हैं। दक्षिण एशियाई देशों में, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देश नवीनतम सूची में भारत से बेहतर स्थान पर हैं। हमें सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाले इस अहम कारक की ओर ध्यान देना होगा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है।

कुँवर राज अस्थाना

भाजपा के सांसद भी स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस की चिंताएं वाजिब हैं- यशपाल आर्य

यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष

यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। जीरो करप्शन का नारा देने वाली सरकार ऊंपर से लेकर नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। श्री आर्य ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया जिससे कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रदेश में शासन-प्रशासन की मिली भगत से धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन के आरोप की पुष्टि होती है ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस निरंतर इस बात को उठाती आ रही है कि उत्तराखंड में जीवनदायिनी नदिया अवैध खनन का शिकार हो रही है और भारी भरकर मशीनों से नदी का सीना चीरा जा रहा है। बड़ा सवाल यही है की शासन प्रशासन क्यों इन खनन माफियाओ के आगे नतमस्तक है। जब निमयवाली में नदियों में मशीनों से खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो फिर प्रदेश में पोकलैंड मशीनों से यह अवैध खनन कैसे चल रहा है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है। आखिर कहां सो रही है जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार..?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र में अवैध खड़िया खनन के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को उजागर करता है कि सरकार और प्रशासन किस हद तक भ्रष्टाचार और लापरवाही में डूबे हुए हैं। पर्यावरणीय क्षति, घरों में आई दरारों और प्रभावित ग्रामीण ों की पीड़ा के बावजूद सरकार ने आंखें मूंदे रखीं। जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय, अधिकारी कमीशन खाने और अपनी जिम्मेदारियों से बचने में व्यस्त रहे। हाईकोर्ट का खनन पर रोक जारी रखना और 160 खनन पट्टाधारकों को नोटिस जारी करना एक बड़ा कदम है।

श्री आर्य ने कहा कि उत्तराखण्ड में सरकार ने रिवरबेड माइनिंग (नदी के तल में खनन) करने वालों से रॉयल्टी और दूसरे टैक्स वसूलने और अवैध खनन पर लगाम लगाने का कार्य और शक्यिां निजी हाथों में सौंप दी हैं। खनन रॉयल्टी संग्रह का काम के लिए हैदराबाद स्थित निजी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनी ने चार बड़े जिलों - नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में पांच सालों तक रॉयल्टी इकट्ठा करेगी। कंपनी राज्य को इस काम के बदले 303.52 करोड़ रुपए देगी। बाकी लाभ का सारा पैसा कंपनी के खाते में जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि उत्तराखंड में अवैध खनन जुर्माना की 1386 करोड़ की वसूली सरकार नहीं कर पाई। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकारी एजेंसियों ने ही अवैध खनन कराया है तथा खनन विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग, जैसी संस्थाए अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने में किल रही हैं। श्री आर्य ने कहा कि सरकार के ही संरक्षण में यदि अवैध खनन पालित-पोषित हो तो माफियाओं को डर किस बात का। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

100 ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी 32वें स्थान पर

प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने जारी की साल 2025 की रैंकिंग

प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वीं रैंक हासिल हुई है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी पिछले साल 61वें स्थान पर थे, इस तरह मुख्यमंत्री की रैंक में जबरदस्त उछाल आया है।

रैंकिंग का आधार

यूसीसी: अन्य राज्यों के लिए बनी ब्ल्यू प्रिंट

इंडियन एक्सप्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले एक साल के कार्यकाल को आधार बनाया है। जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अखबार के मुताबिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए ब्ल्यू प्रिंट की तरह काम कर रही है, इसके बाद, गुजरात ने भी अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है।

राजनैतिक स्थिरता

इंडियन एकसप्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में राजनैतिक स्थिरता कायम करने का भी श्रेय दिया है। अखबार के मुताबिक उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच तीन- तीन मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में राजनैतिक स्थिरता लौट आई है। अखबार ने राष्ट्रीय खेलों के जरिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ की है।

चुनावी सफलता

अखबार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम काज का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि, उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार सफलता हासिल की है, अब उनका लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव है।

इसलिए महत्वपूर्ण है लिस्ट

इंडियन एक्सप्रेस समूह हर साल देश के 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, उद्योग-कारोबार, सिनेमा, खेल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को उनके कार्यों और इसके असर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस साल की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर गृहमंत्री अमित शाह, चौथे स्थान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को रखा गया है। साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अड़ानी, जय शाह, एनएसए अजित डोभाल, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय, अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेताओं को स्थान प्रदान किया गया है।

धामी सर्वाधिक युवा प्रभावशालियों में

अखबार की लिस्ट में 49 वर्षीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वां स्थान प्रदान किया गया है। इस लिस्ट में 50 वर्ष से कम उम्र की बहुत कम राजनीतिक हस्तियां हैं जिनमें सीएम धामी भी हैं।

सरकार द्वारा कॉलेजों में छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करना एक अच्छा कदम इसे निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू करवाए: डॉ सुनील अग्रवाल

डॉ सुनील अग्रवाल

निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ सुनील अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के कॉलेजों में छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं जाने को शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम बताया उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों में कक्षा में उपस्थित होने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है ऐसे में सरकारी आदेश से छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा लेकिन यह व्यवस्था निजी विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित करवाया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में छात्र निजी कॉलेजों के बजाय निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आकर्षित होंगे क्योंकि निजी विश्वविद्यालय में पास होने की भी और कक्षा में छूट की भी गुंजाइश बनी रहेगी जब तक निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की 75% उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी तब तक शिक्षा में सुधार की उक्त कवायद अधूरी रह जाएगी उन्होंने कहा की छात्रों की 75% उपस्थिति निजी विश्वविद्यालयों में और सरकारी कॉलेजों में पहले शुरू की जाए जिससे छात्रों में कक्षा में उपस्थित होने की बाध्यता समझ में आए अन्यथा की स्थिति में छात्र प्राइवेट कॉलेजों में जब उपस्थिति कम होने पर छात्रों को परीक्षा से रोका जाएगा तो छात्र अपनी कमी बताने के बजाय कॉलेज पर अतिरिक्त फीस मांगने का आरोप लगाएंगे ऐसी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और छात्र निजी विश्वविद्यालयों की ओर अग्रसर होंगे वैसे भी छोटे से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की भरमार हो चुकी है जिसके कारण अधिकांश कॉलेज छात्रों की कमी के कारण छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षा को मानने के लिए मजबूर हैं क्योंकि अभिभावक भी कई बार अपेक्षा रखते हैं की छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं होगा इसलिए वर्तमान शिक्षा में सुधार की कवायद तभी सार्थक होगी जब इसे निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू करवाया जाए।

मंत्रिमंडल विस्तार की 'गुड न्यूज' लेकर चारधाम यात्रा के बंदोबस्त में जुटे सीएम धामी

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पखवाड़े में तीन बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। जब-जब सीएम धामी दिल्ली गए तब उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर पकड़ने लगती हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार किस तारीख को होगा इस पर मुहर नहीं लग सकी है। दिल्ली से मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून पूरे जोश के साथ लौटते हैं लेकिन 'गुड न्यूज' अपने पास रखें हुए हैं। हालांकि उनके चेहरे पर कैबिनेट विस्तार जल्द होने के भाव-साफ तौर पर देखे जाते हैं। इसी चैत्र नवरात्रि में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अच्छी न्यूज सुना सकते हैं। बदली परिस्थितियों में कामकाज के बोझ को देखते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार आवश्यक हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले साल चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही श्रद्धालुओं को भारी जाम और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार चार धाम यात्रा बहुत ही कड़े नियमों के साथ शुरू होने जा रही है। पहले एक महीने चारों धामों में वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। रील बनाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धामी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है।

उत्तराखंड की धामी सरकार में बीस दिनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देहरादून से दिल्ली तक माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी तक धामी सरकार का मंत्रिमंडल का आकार बड़ा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पखवाड़े में तीन बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। जब-जब सीएम धामी दिल्ली गए तब उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर पकड़ने लगती हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार किस तारीख को होगा इस पर मुहर नहीं लग सकी है। दिल्ली से मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून पूरे जोश के साथ लौटते हैं लेकिन 'गुड न्यूज' अपने पास रखें हुए हैं। हालांकि उनके चेहरे पर कैबिनेट विस्तार जल्द होने के भाव-साफ तौर पर देखे जाते हैं। इसी चैत्र नवरात्रि में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अच्छी न्यूज सुना सकते हैं। राज्य भाजपा नेताओं को भी कौन-कौन नए मंत्री बनेंगे और किसका पत्ता कटेगा, बेसब्री से इंतजार है। हाईकमान ने भले ही अभी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की मुहर न लगाई हो लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। पूरी संभावना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों के रिक्त पदों की संख्या पांच हो गई है। धामी कैबिनेट में पांच जगह खाली होने से मंत्रियों पर भी मंत्रालयों का बोझ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा विभाग इस वक्त खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं। दरअसल, उत्तराखंड में बीते काफी समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी साफ किया है कि प्रदेश में कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। धामी मंत्रिमंडल का आकार वर्तमान में सात रह गया है। मंत्रिमंडल में पांच मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी संभव है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। जो संकेत मिल रहे हैं, वे इशारा कर रहे हैं कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल में रिक्त पदों पर पांच नए चेहरों को जगह मिल सकती है। भाजपा अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व वितरण को अहम माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह इन दिनों अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जश्न के माहौल में है। सीएम धामी जिलों में जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं एक महीने बाद 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के बंदोबस्त में मुख्यमंत्री धामी जुट गए हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही श्रद्धालुओं को भारी जाम और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए मुख्यमंत्री

धामी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार चार धाम यात्रा बहुत ही कड़े नियमों के साथ शुरू होने जा रही है।

इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत में वीआईपी दर्शन पर रोक, रील बनाने पर भी प्रतिबंध

अगले महीने 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार हर रोज कुछ न कुछ नए दिशा-निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने पिछली बार चार धाम यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए इस बार पहले एक महीने चारों धामों में वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चार धाम यात्रा शुरू होते ही पहले दो महीने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके साथ तीर्थ यात्रियों में वीआईपी दर्शन को लेकर भी भारी नाराजगी भी दिखाई पड़ती रही है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब शुरुआत की एक महीने तक चारों धामों में वीआइपी दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं यात्रा के संबंध में अब तक की सभी विभागों की तैयारियों के संबंध में 5 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है जिसमें तैयारी की समीक्षा की जाएगी। गढ़वाल आयुक्त विजय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा रूट पर पर्याप्त वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं ने 7000 के करीब निजी और कॉमर्शियल वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराए है। वही क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग के 10 किलोमीटर के एरिया को एक सेक्टर में बांटा गया है। जहां 24 घंटे पुलिस कर्मियों निगरानी रहेगी। बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू की जाएगी 15 अप्रैल से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्री ऑनलाइन पूजा बुकिंग करा सकेंगे इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वालों और यूटयूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ-बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12 हजार फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था। यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिन तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में यह शोर गूंजता रहा। इसी तरह, पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी धामों पर बंद रहेगी। इस साल 30 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। इसी दिन सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आखिर में 4 मई को विधि-विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्ण रूप से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की एडवाइजरी

इस बार राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर.राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों में चारधाम यात्रा 2025 को सुरक्षित और स्वास्थ्य-संबंधी दृष्टि से बेहतर बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जो तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श एवं एसओपी जारी कर दी है। डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और चिकित्सकीय तैयारियों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। विशेषकर, बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री जैसे ऊंचे-चढ़ते क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों को कठोर जलवायु, निम्न ऑक्सीजन स्तर एवं कठिन मार्ग स्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए तीर्थयात्री जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यक तैयारियों के साथ आएं। आपातकालीन सेवाएं और हेलीपैड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर तीर्थयात्रियों की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यापक परामर्श को सभी राज्यों में पत्र भेजकर संभावित तीर्थयात्रियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चारधाम यात्रा को पूरी तरह सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य की देखभाल सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी है, जिसके अनुसार यात्रा से पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराएं। कम से कम दो माह पूर्व पैदल चलने, प्राणायाम एवं हृदय संबंधी व्यायाम अपनाएं। आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा साथ रखें। स्वास्थ्य एवं पर्यटन पंजीकरण ऐप पर अनिवार्य पंजीकरण करें। पर्याप्त जल, संतुलित आहार एवं हल्के गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। हल्की परतों वाले कपड़े, गरम वस्त्र, दस्ताने एवं ऊनी सामग्री साथ रखें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन लेवल सहित 28 पैरामीटर की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। यह सभी प्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्वाइंट के साथ जोड़े गए हैं ताकि यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों की पूरी स्वास्थ्य जांच हो सके। यात्रा मार्ग पर मेडिकल रिलीफ प्वाइंट की संख्या बढ़ाई गई है और वहां पर डॉक्टरों के साथ प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की जाएगी। केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा के दौरान हर एक से दो घंटे में 5-10 मिनट का विश्राम करें। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर साथ रखें। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह से ग्रसित यात्री अपनी जरूरी दवाइयां और डॉक्टर का नंबर साथ रखें। यदि यात्रा के दौरान सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर या उल्टी महसूस हो तो तुरंत निकटतम मेडिकल रिलीफ प्वाइंट पर जाएं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें केदारनाथ यात्रा मार्ग के दौरान आती हैं। यात्रा मार्ग पर 10 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और दो पीएचसी सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड और नारायणकोटी में हेल्थ एटीएम लगाकर यात्रियों की फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। यहां पर ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन लेवल, वजन, लंबाई और शरीर का तापमान मापा जा सकेगा। साथ ही, टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी तीर्थयात्री भाषा की वजह से जरूरी स्वास्थ्य जानकारी से वंचित न रहे। इसलिए एडवाइजरी को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी और असमिया सहित 12 भाषाओं में जारी किया गया है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने फिर छुड़ाए 'पसीने'

पिछले साल 2024 में पड़ी भयंकर गर्मी को देशवासी भूल नहीं पाए हैं। मैदानी राज्यों के साथ पहाड़ों पर भी पारा चढ़ गया था। अपने शानदार क्लाइमेट के लिए देश भर में मशहूर देहरादून भी चिलचिलाती गर्मी से बिलबिला गया था। देश के लोगों को अनुमान था कि इस बार गर्मी का असर कुछ कम रहेगा। इस साल 2025 में पड़ने वाली गर्मी को लेकर पिछले काफी समय से मौसम विभाग भी चुप बैठा था। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पड़ने वाली गर्मी की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने साल 2024 से भी ज्यादा इस बार भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होनी की आशंका है। शंभू नाथ गौतम

भगवान न करें इस साल मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही हो। हम बात कर रहे हैं देश में शुरू होने वाली गर्मी और हीट वेव को लेकर। गर्मी का नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसके साथ दोपहर में घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई राज्यों में गर्मी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक भीषण गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है। पिछले साल 2024 में पड़ी भयंकर गर्मी को देशवासी भूल नहीं पाए हैं। मैदानी राज्यों के साथ पहाड़ों पर भी पारा चढ़ गया था। अपने शानदार क्लाइमेट के लिए पूरे देश भर में मशहूर देहरादून भी चिलचिलाती गर्मी से बिलबिला गया था। देश के लोगों को अनुमान था कि इस बार गर्मी का असर कुछ कम रहेगा। इस साल 2025 में पड़ने वाली गर्मी को लेकर पिछले काफी समय से मौसम विभाग भी चुप बैठा था। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पड़ने वाली गर्मी की भविष्यवाणी की है । आईएमडी ने साल 2024 से भी ज्यादा इस बार भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिन्हें गर्मी के नाम से ही घबराहट होने लगती है। उनके लिए मौसम विभाग की यह चेतावनी जरूर चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी देश के अलग-अलग राज्यों के लिए है। इस बार मैदानी राज्यों में एक बार फिर गर्मी झुलसाने के लिए तैयार है। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीटवेव (लू) के दिनों की संख्या दोगुनी होनी की आशंका है। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिन के कई लूप आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल कितने दिन हीटवेव का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक, देश के आठ राज्यों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। मार्च से ही कई राज्यों में हीटवेव जैसी स्थितियां बनने लगी है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ सकती है।

आईएमडी के मुताबिक, इस साल पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी

आईएमडी की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने स्पष्ट करते हुए कहा, हमें सामान्य से थोड़ी अधिक गर्मी पड़ने की उम्मीद है, खासकर पश्चिम और मध्य भारत में। आम तौर पर, उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 5 से 6 दिन गर्मी के दिन देखे जाते हैं। इस साल, हमें 10 से 12 दिन की उम्मीद है, जो सामान्य से दोगुना है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक मौसमी पूर्वानुमान है और इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम के सभी दिन सामान्य से अधिक होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि पूर्वानुमान मौसमी पैमाने पर सामान्य से अधिक गर्मी का संकेत देता है, लेकिन आईएमडी अधिक सटीक स्थानीय बदलाव प्रदान करने के लिए विस्तारित-सीमा और दैनिक पूर्वानुमानों के साथ पूर्वानुमानों को

अपडेट करना जारी रखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, हीटवेव के दिन बढ़ने के पीछे की वजह अल-नीनो परिस्थितियां है। प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से अल-नीनो परिस्थितियां बनती हैं। इससे भारत में बारिश में कमी आती है और गर्मी का असर तेज होता है। इस साल अल-नीनो का सबसे खराब दौर ढाई महीने तक चलेगा, जो जून में खत्म होगा। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। इसके चलते लू ज्यादा दिनों तक चलती है, जिससे हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ जाती है। गौरतलब है कि देश में गर्मी के मौसम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला प्री समर, मार्च और अप्रैल में गर्मी की शुरुआत होती है। अप्रैल के पहले सप्ताह से लू चलने के साथ ही गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा पीक समर, मई और मध्य जून में गर्मी पीक पर होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे पूरे देश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। तीसरा पोस्ट समर, जून के आखिरी सप्ताह से गर्मी थोड़ी कम होने लगती है। जैसे-जैसे मानसूनी हवाएं देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। कई बार मानसून चक्र में बदलाव की वजह से जुलाई महीने में भी भीषण गर्मी पड़ती है।

उत्तराखंड में पिछले साल गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, तापमान 43 पार पहुंच गया था

पिछले साल मई-जून में उत्तराखंड का पारा भी चढ़ा दिया है। मैदानी जिलों और पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन बनी रही। देहरादून समेत पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर गर्म हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में पिछले 157 सालों में पहली बार तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 जनवरी 1867 से मौसम विभाग देहरादून में तापमान की गणना कर रहा है। तब से पहली बार साल 1988 में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था। उस साल देहरादून का अधिकतम तापमान 42.8 दर्ज किया गया था। उसके बाद 2012 में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया और अब 31 मई 2024 को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

अब बैंक खाते या एफडी में 'चार नॉमिनी' बनाने का होगा अधिकार

बजट सत्र के दौरान 26 मार्च को केंद्र सरकार ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जो सीधे ही बैंकिंग और ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों होगा जो बैंक खातों और एफडी आदि में एक नॉमिनी बनाने को लेकर कुछ परेशान थे। अब सरकार ने चार लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दे दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया, जिससे बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। लोकसभा ने इस विधेयक को 3 दिसंबर, 2024 को पहले ही पारित कर दिया था। यह ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान बनाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया, जिससे बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

केंद्र सरकार ने अब बैंक में खाते खुलवाने या एफडी कराने में एक नॉमिनी का नियम खत्म कर दिया है। अब बैंक के ग्राहक कम से कम चार नॉमिनी का नाम दे सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को जरूर फायदा होगा। बजट सत्र के दौरान 26 मार्च को केंद्र सरकार ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जो सीधे ही बैंकिंग और ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों होगा जो बैंक खातों और एफडी आदि में एक नॉमिनी बनाने को लेकर कुछ परेशान थे। अब सरकार ने चार लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दे दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया, जिससे बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। लोकसभा ने इस विधेयक को 3 दिसंबर, 2024 को पहले ही पारित कर दिया था। यह ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान बनाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया, जिससे बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इसको पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने पारित कर दिया था। इस विधेयक का उद्देश्य शासन मानकों में सुधार करना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को बैंकों की रिपोर्टिंग में निरंतरता सुनिश्चित करना है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप अपने बैंक खाते या एफडी के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बैंकों में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में भारी कमी बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आई है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पांच अलग-अलग अधिनियमों को प्रभावित करेगा, जो इसे अद्वितीय बनाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधयेक इसलिए भी अद्वितीय है, क्योंकि आठ टीमों ने इसके संशोधनों पर काम किया है, जिससे बजट भाषण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित हुए हैं।

बैंकिंग कानून संशोधन बैंक के ग्राहकों को देगा कई अधिकार

राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस विधयेक में नकद और सावधि जमा के लिए एक साथ नामांकन की अनुमति है। हालांकि, लॉकर के मामले में केवल एक साथ नामांकन की अनुमति है। इसके अलावा बीमा पॉलिसियों और अन्य वित्तीय साधनों में इसका पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहा कि अगर आप पिछले पांच सालों पर नजर डालें तो पाएंगे कि प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी से

जुड़े करीब 112 मामलों को अपने हाथ में लिया है, जिनमें जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 55 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 55 फीसदी महिलाओं के पास हैं। उन्होंने सदन को बताया कि 2023 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी रिपोर्ट कहती है कि डीपीआई का लाभ उठाकर भारत ने 80 फीसदी से अधिक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसे पारंपरिक तरीकों से हासिल करने में 47 साल लग जाते। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में विफल है। बता दें कि बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों में से विधेयक जमाकर्ताओं को अपने बैंक खातों या सावधि जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जो वर्तमान एकल-नामित प्रणाली की जगह लेता है। इस कदम का उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु के बाद निधि वितरण को सरल बनाना है, जो एक समस्या है जो कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई थी। बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 अब संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इससे बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होंगे, जो ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान बनाएगा। इसके कानून बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव है कि अब आप अपने बैंक खाते या एफडी के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे पहले ग्राहकों को सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाने का प्रावधान था।

एक मई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा

एटीएम से पैसे निकालने वाले ग्राहकों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। अगर आप भी कैश के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभी एक लिमिट तक आप एटीएम से पैसे फ्री में ही निकाल सकते हैं। लेकिन लिमिट के बाद आपको चार्ज देना पड़ता है। 1 मई से यहीं चार्ज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको एटीएम से कैश निकालना और महंगा पड़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बदलाव देश की केंद्रीय बैंक, आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ने मिलकर किया है। इस बदलाव के तहत 1 मई 2025 से एटीएम मशीन से कैश निकालने पर लगने वाला चार्ज बढ़ सकता है। अभी हमें कैश निकालने पर 17 रुपये चार्ज देना होता है, जिसे 1 मई से बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन जैसे मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक के लिए भी अभी 6 रुपये चार्ज लगता है, जिसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार, यदि आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह शुल्क तब लागू होगा जब आपकी बैंक द्वारा निर्धारित फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट समाप्त हो चुकी होगी। मेट्रो शहरों में, दूसरे बैंक के एटीएम से पांच फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाती है। वहीं, नॉन-मेट्रो शहरों में यह लिमिट तीन ट्रांजैक्शन की है। इसके बाद आपको बढ़ी हुई फीस का भुगतान करना होगा। बढ़ी हुई इंटरचेंज फीस से खासकर छोटे बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है। छोटे बैंक अपने सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दूसरे बड़े बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसे में यह शुल्क वृद्धि इन बैंकों की लागत को बढ़ा सकती है, जो उनकी सेवाओं के लिए एक चुनौती हो सकती है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

एलयूसीसी के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश

- **लुक आउट सर्कुलर/रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के निर्देश, ईडी और आयकर विभाग को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट**
- **मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खातें करें फ्रीज तथा सम्पत्ति करें अटैच**

26 मार्च, 2025 को श्री वी. मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों के साथ राज्य में लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट कोपरैटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) के संचालकों के विरूद्ध पंजीकृत कुल 07 अभियोगों में की गयी पुलिस कार्यवाही की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान जांच में तेजी लाने, अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने तथा पीड़ितों के शिकायती प्रार्थना पत्रों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य में लगभग 35 शाखाओं के मुख्य संचालक समीर अग्रवाल (निवासी मुम्बई), पंकज अग्रवाल (निवासी मध्यप्रदेश), एवं शबाब हुसैन (निवासी उत्तर प्रदेश) आदि के विदेश भागने की संभावना को ध्यान में रखते हुए लुक आउट सर्कुलर/रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक कार्यवाही हेतु इंटरपोल की सहायता ली जाए। साथ ही, जो अभियुक्त उत्तर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध हैं, उन्हें वारंट बी पर लाकर नियमानुसार पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाए एवं निवेशकों की संपत्ति बरामद की जाए और इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को अधिग्रहित किया जाए। पंजीकृत अभियोगों की विस्तृत रिपोर्ट, प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग, भारत सरकार के स्थानीय कार्यालयों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मनी ट्रेल के आधार पर अभियुक्तों के बैंक खातों को फ्रीज करने की भी कार्यवाही की जाए। विवेचना के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) से अभिलेख प्राप्त कर, साक्ष्य के आधार पर UPID Act अथवा BUDS Act के तहत भी अभियोग पंजीकृत किए जाएं, ताकि निवेशकों एवं पीड़ितों की धनराशि लौटाने हेतु सक्षम अधिकारी से पत्राचार किया जा सके। गोष्ठी में श्री नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री धीरेन्द्र गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्री यशवंत चौहान, पुलिस अधीक्षक सीआईडी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून डोईवाला टोल प्लाजा में हुई दुर्घटनाः एक गंभीर सड़क सुरक्षा का सवाल

शीशपाल गुसाई

आजकल, सड़क पर चलते समय किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गया है। सड़क पर मौत का मंजर वास्तव में चिंताजनक है, जहाँ किसी की भी गाड़ी अचानक ही बेकाबू ट्रक/ डम्फर से टकरा सकती है। इसे देखने वाले लोग सिर्फ भीषण दृश्य के गवाह बनते हैं, लेकिन वे इस भयावहता को रोकने में असमर्थ रहते हैं।

आज, सोमवार पौने आठ बजे सुबह देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा में हुई एक दुर्घटना ने न केवल दो मूल्यवान जीवन छीन लिए, बल्कि सड़क सुरक्षा के मसले पर गंभीर चिंताएं भी उत्पन्न की हैं। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक ट्रक/ डम्फर, बगैर ब्रेक लगाए, तेजी से दो लोगों की लाल कार को टक्कर मारता है। और यह कार टोल प्लाजा के विशाल लोहे के खम्बे में चकनाचूर हो जाती है। पिचक जाती है। इस हादसे में जिला न्यायालय नई टिहरी में कार्यरत पंकज पंवार, पेशकार और रतनमनी उनियाल, प्रशासनिक अधिकारी, की दुखद मृत्यु हो गई। पंवार थान गांव जौनपुर टिहरी, उनियाल चन्द्रबदनी टिहरी के मूल निवासी थे। उनका हाल निवास देहरादून रिंग रोड छह नम्बर पुलिया (अब महाराजा प्रद्युम्न शाह चौक) के आसपास था।

यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों कर्मचारी अपनी कार में रविवार की छुट्टी के बाद घर देहरादून से नई टिहरी लौट रहे थे। लगभग सुबह पौने 8 बजे के करीब, जब वे टोल प्लाजा डोईवाला में अनुशासन के साथ चल रहे थे, तब पीछे से आया डम्फर/ ट्रक उन्हें ठोकते हुए आगे बढ़ गया। दर्दनाक बात यह है कि इस दुर्घटना के कारण दोनों की बॉडी को काटकर बाहर निकाला गया, जो घटना की भयावहता को दर्शाता है। सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या ट्रक/ डम्फर की तकनीकी जांच की गई थी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ट्रक के रखरखाव पर ध्यान दिया गया था? यदि ट्रक का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति कैसे दी गई थी? यह स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने के कारण ही यह भीषण दुर्घटना हुई है।

घटना के बाद, टोल प्लाजा में अफरा-तफरी मच गई, और सवाल उठने लगे कि आखिर सड़क पर ऐसी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है, और लोगों ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोग तो उसकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं, यह बताते हुए कि ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दुर्घटना से यह बात साफ होती है कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा और तकनीकी जांच एक अनिवार्य आवश्यकता है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण न केवल दो परिवारों का सुख-शांति छिन गया बल्कि समाज को भी एक गहरा आघात पहुंचा। जब तक हम सड़क सुरक्षा के प्रति सजग नहीं होंगे, ऐसी दुखद घटनाएं हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनकर सामने आती रहेंगी। इसलिए, हमें इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को रोका जा सके।

यह घटना केवल एक उदाहरण है जो सड़क सुरक्षा की खामियों को उजागर करता है। बेकाबू ट्रकों और डम्फरों का दौड़ना सड़क पर मौजूद अन्य वाहनों के लिए एक बड़ा डर बन चुका है। राज्य और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे इन मुद्दों पर ध्यान दें और ठोस कदम उठाएँ। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, कठोर नियमों का पालन, और जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल घटनाओं को देखने पर निर्भर रहेंगे तो नुकसान और बढ़ेगा, इसलिए हमें अपने आसपास के माहौल में सक्रिय रहकर बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। सड़कों पर हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक संगठित प्रयास की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक सदस्य को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझना होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जब तक हम यह मानसिकता नहीं बनाएँगे, तब तक सड़कें खतरनाक बनी रहेंगी और मानव जीवन का नुकसान होता रहेगा।

विनाशकारी भूकंप ने म्यांमार-थाईलैंड के कई शहरों को किया तहस-नहस

म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार 28 मार्च दोपहर 11रू50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भयंकर भूकंप ने एक झटके में हजारों लोगों की जान ले ली। दोनों देशों में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें, पुल ध्वस्त हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10 हजार से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34: यानी सबसे ज्यादा है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिका, भारत समेत कई देश दोनों देशों की मदद करने के लिए आगे आए हैं।

म्यांमार और थाईलैंड के लोग 28 मार्च साल 2025 का दिन कभी नहीं भुला सकेंगे। यह इतनी बड़ी घटना है कि इसमें विनाशकारी, आपदा, खौफनाक मंजर, तबाही और त्रासदी शब्द भी कम पड़ गए। भयंकर भूकंप ने एक झटके में हजारों लोगों की जान ले ली। दोनों देशों में भारी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा म्यांमार में चारों ओर तबाही का मंजर है। भूकंप की वजह से कई ऊंची-ऊंची बिल्डिंग भर भरभरा कर गिर गई। म्यांमार और थाईलैंड में कई इमारतें, पुल ध्वस्त हो गए। म्यांमार में हजारों लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। यह देश दुनिया से मदद मांग रहा है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की खबर पूरे दुनिया भर में ट्रेंड हुई। भारत समेत कई देश दोनों देशों की मदद के लिए आगे आए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में दहशत का माहौल है। दोनों देशों में राहत बचाव कार्य जारी है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 144 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 732 लोग घायल हैं। उधर, थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 154 लोगों ने जान गंवाई है। थाइलैंड में सभी एक लाख भारतीय पर्यटक सुरक्षित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रभावितों की कुशलता की कामना कर मदद की पेशकश भी की। पीएम मोदी 3 अप्रैल को थाइलैंड में बिमस्टेक संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वहीं म्यांमार सरकार के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्तदान की अत्यधिक आवश्यकता है। सैन्य सरकार ने विदेशी सहायता स्वीकार करने की घोषणा की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभिक राहत कार्यों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि जारी की है। वहीं चीन और रूस ने म्यांमार में बचाव दल भेजे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अमेरिकी मदद की बात कही है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10 हजार से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34: यानी सबसे ज्यादा है। भारत में कोलकाता, इंफाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए।

म्यांमार और थाईलैंड में 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप घोषित किया गया

म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टरशॉक आया। वहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। यहां पर 400 लोग काम कर रहे थे, जिनमें 80 से ज्यादा लापता हैं। 3 लोग मारे गए। म्यांमार में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं, लेकिन हर तरफ मलबे का ढेर, टूटी सड़कें, और ढही इमारतें नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि, अस्पतालों में घायलों की तादाद भी हजारों में है। इस विनाशकारी भूकंप ने मंडाले, नेपिटॉ, यांगून और कई अन्य शहरों में इमारतों, पुलों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे अधिक मौतें नेपिटॉ में हुई हैं। यहां से 90 से अधिक लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इस भूकंप का प्रभाव महसूस किया गया। यहां एक 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत पूरी तरह गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया, लोग घबराकर चीखने लगे और सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई। थाईलैंड सरकार ने इसे 'भयानक त्रासदी' करार दिया और कहा कि अभी भी कुछ लोगों के जीवित होने की उम्मीद है। ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र की आबादी 1.70 करोड़ से अधिक है जिनमें से कई लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक की ऊंची इमारतों एवं होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में 'स्वीमिंग पूल' में पानी में लहरें उठती दिखीं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप आए हैं। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज्यादा भूकंप आए थे। यह विनाशकारी भूकंप म्यांमार और थाईलैंड को बहुत गहरे जख्म दे गया है जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो सकेगी।

5 फ़िल्म फ़ेस्टिवल, जिनमें हर युवा फ़िल्म निर्माता और सिनेमा प्रेमी को ज़रूर शामिल होना चाहिए

दीक्षा ग्रोवर

अगर आपको सिनेमा से प्यार है और फिल्में सिर्फ़ देखने से ज़्यादा बनाना और समझना चाहते हैं, तो फिल्म फेस्टिवल्स आपके लिए एक सपना सच होने जैसा है। ये सिर्फ़ ग्लैमरस इवेंट्स नहीं होते, बल्कि नए फिल्ममेकर्स के लिए दरवाजे खोलने और प्रेरणा पाने की बेहतरीन जगह होते हैं। दुनिया में कई ऐसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल हैं, जो सिनेमाई ट्रेंड सेट करते हैं और जहां करियर बनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाएँ, तो ये रहे वो पाँच फिल्म फेस्टिवल, जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए!

1. कान्स फिल्म फेस्टिवल (फ्रांस)-ग्लैमर और ग्रेटनेस का संगम

कब और कहाँ: कान्स, फ्रांस|मई

कान्स सिर्फ़ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ आने वाली फ़िल्में दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं और अगर आपकी फिल्म यहाँ दिखाई गई, तो समझिए आपका नाम इंडस्ट्री में छप गया। पल्प फिक्शन से लेकर पैरासाइट तक, कई आइकॉनिक फ़िल्में यहीं से निकली हैं।

इसमें जाने की बड़ी वजहें:

• टॉप क्लास प्रीमियर-विश्व की बेहतरीन फ़िल्में सबसे पहले यहाँ दिखाई जाती हैं।

• फिल्म आइकन्स से सीखें-हर साल बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स मास्टरक्लास देते हैं।

• नेटवर्किंग का स्वर्ग-इंडस्ट्री के बड़े लोग यहीं डील्स साइन करते हैं।

किस्सा: 2019 में, बोंग जून-हो की 'पैरासाइट' ने यहाँ 8 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन पाया और फिर ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया!

2. वेनिस फिल्म फेस्टिवल (इटली)-जब सिनेमा कला बन जाता है

कब और कहाँ: वेनिस, इटली|अगस्त के अंत में-सितंबर की शुरुआत में यह दुनिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है और यहाँ सिनेमा को कला के रूप में देखा जाता है। अगर आपकी फिल्म यहाँ प्रदर्शित होती है, तो समझिए आपने इंडस्ट्री में आधा सफर तय कर लिया।

क्यों जाएँ?

• अवार्ड सीज़न का बिगिनिंग पॉइंट - कई ऑस्कर विनिंग फ़िल्में यहीं से शुरुआत करती हैं।

• मैजिकल सेटिंग-वेनिस की खूबसूरत नहरों के बीच फिल्म देखना एक अलग ही अनुभव देता है।

• बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा-यहाँ आपको ऐसी फ़िल्में मिलेंगी जो मुख्यधारा से हटकर होती हैं।

किस्सा: अल्फोंसो क्वारोन की 'रोमा' ने यहाँ गोल्डन लायन जीता और बाद में ऑस्कर भी अपने नाम किया!

3. टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF)-फिल्म प्रेमियों का फेस्टिवल

कब और कहाँ: टोरंटो, कनाडा|सितंबर

अगर कान्स और वेनिस थोड़ा एक्सक्लूसिव लगता है, तो TIFF आपका फेस्टिवल है! यहाँ दर्शकों का बहुत बड़ा रोल होता है और यही वजह है कि इसे 'पीपल्स फेस्टिवल' कहा जाता है।

क्या खास है?

• सभी के लिए खुला-फिल्म देखने के लिए आपको इंडस्ट्री पास की ज़रूरत नहीं!

• ऑस्कर इंडिकेटर-जो फिल्म यहाँ पीपल्स च्वाइस अवार्ड जीतती है, वो अक्सर ऑस्कर भी जीतती है।

• हॉलीवुड और इंडी फ़िल्मों का परफेक्ट बैलेंस-यहाँ आपको दोनों देखने को मिलेंगी।

किस्सा: 2013 में '12 इयर्स ए स्लेव' ने यहाँ पीपल्स च्वाइस अवार्ड जीता और कुछ महीनों बाद ऑस्कर भी!

4. सनडांस फिल्म फेस्टिवल (यूएसए)-इंडी फिल्मों का पावरहाउस

कब और कहाँ: पार्क सिटी, यूटा, यूएसए|जनवरी

अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर बनना चाहते हैं, तो यह फेस्टिवल आपके लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं। क्रिस्टोफर नोलन, क्वेंटिन टारनटिनो और जॉर्डन पील जैसे कई दिग्गज यहीं से उभरे हैं।

क्यों जाएँ?

• इंडी फिल्मों का मक्का-यहाँ कम बजट वाली लेकिन दमदार फ़िल्मों को पहचान मिलती है।

• युवा फिल्ममेकर्स के लिए बढ़िया माहौल-यहाँ बड़े बजट की फिल्मों की चमक-दमक से ज़्यादा कंटेंट की अहमियत होती है।

• नेटवर्किंग का शानदार मौका-प्रोडयूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नई आवाज़ों की तलाश में रहते हैं।

किस्सा: 1992 में, टारनटिनो की 'रिज़र्वायर डॉग्स' यहाँ दिखाई गई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा!

5. बर्लिनले (बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल)-जब सिनेमा बदलाव लाता है

कब और कहाँ: बर्लिन, जर्मनी|फरवरी

अगर आपको सिनेमा के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों में दिलचस्पी है, तो बर्लिनले से बेहतर कुछ नहीं। यह दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है।

क्या खास है?

• सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित सिनेमा-यहाँ दिखने वाली कई फ़िल्में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं।

• नई आवाज़ों का स्वागत-उभरते हुए फिल्ममेकर्स को यहाँ बहुत मौके मिलते हैं।

• बोल्ड और प्रयोगात्मक फ़िल्मों के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म

किस्सा: 2016 में, शरणार्थी संकट पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'फायर एट सी' ने यहाँ गोल्डन बियर जीता और दुनिया भर में हलचल मचा दी।

तो, आपको कहाँ जाना चाहिए?

कान्स-अगर आप इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनना चाहते हैं।

वेनिस-अगर आपको आर्टहाउस और प्रतिष्ठा का मेल पसंद है।

TIFF-अगर आप फिल्मों और दर्शकों के जुड़ाव को एन्जॉय करते हैं।

सनडांस-अगर आप इंडी फिल्ममेकिंग में उतरना चाहते हैं।

बर्लिनले-अगर आपको सिनेमा से सामाजिक बदलाव की उम्मीद है।

कोई भी फेस्टिवल चुनें, एक बात तय है-यह आपका सिनेमा देखने और समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा!

आईआईटी रुड़की में मलवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'नवाचार नेतृत्व विकास कार्यक्रम' का सफल आयोजन

रुड़की, 26 मार्च 2025- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने 22 से 26 मार्च 2025 तक मलवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (MMTTP) के अंतर्गत 'नवाचार नेतृत्व विकास कार्यक्रम' का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत भर के केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों ने भाग लिया।

इस पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को संस्थागत नेतृत्व, सामूहिक निर्णय लेने, साझा शासन, पहल शुरू करने और समस्या-समाधान जैसे क्षेत्रों में दक्ष बनाना था। कार्यक्रम में प्रबंधन सत्रों, कार्यशालाओं और विशेषज्ञों के साथ संवाद के माध्यम से शिक्षकों को नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे। श्री दीपक कुमार, सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन, संस्कृत शिक्षा एवं जनगणना, उत्तराखंड सरकार प्रो. के. के. पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की, श्री एस. पी. डोभाल, निदेशक, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान और प्रो. एच. सी. पोखरियाल, वरिष्ठ शिक्षाविद्।

श्री दीपक कुमार ने नीतियों के कार्यान्वयन और शासन में नेतृत्व की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग पर बल दिया।

प्रो. के. के. पंत ने अकादमिक वातावरण में एक नेता के गुणों पर चर्चा की, वहीं प्रो.

पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर संवाद किया।

कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चर्चा के प्रमुख विषयों में VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) से निपटना, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु नवाचार नेतृत्व, रचनात्मक डिजाइन सोच, टीम निर्माण और भविष्यदृष्टा नेतृत्व शामिल रहे।

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों के टीम प्रबंधन, संवाद कौशल और समालोचनात्मक सोच को सशक्त बनाना, सहयोग को बढ़ावा देना और प्रशिक्षित संस्थागत नेताओं की एक सशक्त श्रृंखला तैयार करना है। इसके साथ ही, प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने संस्थानों में इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर दूसरों को भी लाभान्वित करें।

मेडिकल प्रोफेशन मानवता की सेवा, पीड़ितों के कष्टों को दूर करने की एक पवित्र जिम्मेदारी है: राज्यपाल

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह सम्पन्न

कुलाधिपति/राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने बुधवार को हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के सातवें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के परिजनों एवं गुरुजनों को इसकी बधाई देते हुए इसे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया।

राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में अधिकांश संख्या बालिकाओं की होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। राज्यपाल ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो समाज में नारी सशक्तीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाकर प्रगति और विकास की राह में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं।

राज्यपाल ने सभी छात्र-छात्राओं को खुली आंखों से सपने देखते हुए उन्हें साकार करने की बात कही। कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर इस संस्था से बाहर निकल रहे हैं, तो आप केवल एक डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ या स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि आप समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं है। यह प्रोफेशन लोगों के दुखों को कम करने, बीमार लोगों का उपचार करने और समाज की भलाई में योगदान देने की पवित्र जिम्मेदारी देता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी छात्र-छात्राएं अपने ज्ञान और कौशल से अपने कार्यक्षेत्र में करुणा, समाज की सेवा और ईमानदारी को बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि आपके पास आने वाला रोगी केवल एक मेडिकल केस नहीं होता है। वह बीमारी से परेशान तथा आशंका और उम्मीद के बीच उलझा हुआ एक इंसान होता है। उसका केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि उत्साहवर्धन भी आवश्यक होता है।

राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनिया आज विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में समर्पित और कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से नवीनतम चिकित्सा ज्ञान के साथ अद्यतन रहने और हर परिस्थिति में मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। कहा कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भी लगातार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की दिशा में कार्य कर रही है। चिकित्सा प्रणाली में अभूतपूर्व प्रगति हो चुकी है और आने वाले समय में अपार संभावनाएं पैदा होती दिख रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी छात्र-छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा में भी पूर्ण दक्षता हासिल होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें उचित अवसर व दिशा दिखाए जाने की जरूरत मात्र है, इसलिए सरकार संकल्पित है। यहाँ के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को किसी प्रकार के संसाधनों व धन कमी आड़े नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है।

अगले डेढ़-दो वर्षों में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बनने से प्रदेश में कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 8 हो जाएगी, जिससे एमबीबीएस करने वाले छात्रों की संख्या एक हजार से अधिक होगी। प्रदेश में 98 नर्सिंग कॉलेज और 100 से अधिक पैरामेडिकल कॉलेज हैं। राज्य सरकार 450 नए डॉक्टर्स नियुक्त करने जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के अपने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता हासिल कर उपाधि प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राएं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अपना तथा प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे।

इस अवसर पर निदेशक एवं सीईओ एम्स ऋषिकेश प्रो. मीनू सिंह, कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो. ओंकार सिंह सहित सभी प्राचार्यगण, संकाय अध्यक्ष, विद्यार्थी एवं अभिभावक गण उपस्थित रहे।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को मिली बड़ी जिम्मेदारी

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष (प्रशासन एवं संगठन) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के विधिवत गठन तक प्रदेश कार्यालय से होने वाली संगठनात्मक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु श्री सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष (प्रशासन/संगठन) के रूप में कार्य करेंगे। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी संचालन में सहयोग करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने कहा कि श्री सूर्यकांत धस्माना लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं और संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके व्यापक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, जिससे प्रदेश कांग्रेस संगठन और प्रशासन को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर समस्त कांग्रेस जनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने सूर्यकांत धस्माना को दी बधाई

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने पार्टी के वरिष्ठ साथी सूर्यकांत धस्माना को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा द्वारा संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी दिए जाने पर बधाई दिए दी है।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि सूर्यकांत धस्माना पूर्णतः इस पद के सुपात्र है और निश्चित ही पार्टी संगठन और पार्टी प्रशासन को इससे नई ऊर्जा मिलेगी!

उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के इस निर्णय को विद्वत्तापूर्ण और दूरदर्शिता पूर्ण बताया।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज उद्योग विभाग द्वारा देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान में हो रही निरंतर वृद्धि के लिए उद्योग विभाग की सराहना की। सीएस ने उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पीस टू प्रोस्पेरीटी के बारे में बताते हुए कहा की उत्तराखंड में वातावरण औद्योगिक अनुकूल है और ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में तीन लाख करोड़ के एमओयू में से नब्बे हजार करोड की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने उत्तराखंड के रणनीतिक निवेश कार्ययोजना की प्रशंसा करते हुए इसे राज्य के लिए बेंचमार्क बताया। उनके द्वारा उद्योग विभाग के यू हब इनवेस्टर मित्र और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसे नवाचारों की सराहना की गई। उन्होंने विभाग को लघु उद्योगों की लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर अधिक निवेश प्राप्त हो सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे मे चर्चा करते हुए बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस में उत्तराखंड टॉपअचीवर, और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर केटेगरी में शामिल है, साथ ही उत्तराखण्ड निर्यात के मामले में हिमालयन राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

सुश्री अंकिता पांडे, निदेशक एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान के लिए विवाद निवारण पर चर्चा की। कार्यक्रम में स्टार्ट अप ग्रांड चैलेंज के उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया। सेतु आयोग के एडवाइजर श्री हनुमंत रावत ने बताया कि सतत विकास के माध्यम से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड में रैंप योजना का शुभारंभ करने के साथ-साथ एक वर्कशाप का आयोजन भी किया गया। एमएसएमई इकाइयों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विश्व बैंक पोषित रैंप योजना के राज्य में आरंभ होने से वैश्विक स्तर पर हमारे उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। उत्तराखंड को रैंप के अंतर्गत 100 करोड़ का बजट आउटले प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में रैंप पोर्टल और एक्सपोर्ट पोर्टल का लॉन्च किया गया। साथ ही गति शक्ति पर एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई।

कार्यक्रम में सचिव श्री विनय शंकर पांडे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक श्री विनम्र मिश्रा, SME लिस्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट श्री हरीश आहूजा, उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों समेत भारत सरकार के अधिकारी व अन्य अतिथि मौजूद रहे।

धामी सरकार के 3 सफल साल, उत्तराखंड देश मे अग्रणी राज्य बनने की ओर चल पड़ा है: डॉ. नरेश बंसल

धामी सरकार मे हुए है देश मे नजीर साबित होने वाले फैसले, भाजपा जो कहती है करती है: डॉ. नरेश बंसल

डॉ. नरेश बंसल

माननीय राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा एवं सासंद राज्यसभा

भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्य सभा डॉ. नरेश बंसल ने आज देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून मे आयोजित भव्य रोड शो व विशाल जन सभा मे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संग प्रतिभाग किया।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा ने देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड मे उत्साह का माहौल है, रोड शौ व जनसभा मे आमजन की भारी सहभागिता सरकार को जनता का पूर्ण समर्थन दर्शाती है क्योंकि भाजपा जो कहती है करती है। आज पूरे प्रदेश मे यही माहौल है सब जगह लोग उत्सव मना रहे है।

डॉ. नरेश बंसल ने प्रदेश की देवतुल्य जनता व भाजपा कार्यकर्ताओ को सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाए दी है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के ओजपूर्ण मार्गदर्शन व संकल्प के धनी युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व मे विकास की बयार उत्तराखंड मे बह रही है, भाजपा सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया है, कर रही है जिससे उत्तराखंड देश मे अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि पिछले सालो मे भाजपा सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक फैसलों से जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी पर हमलों की साजिशों पर पूर्ण विराम लगाया है। सरकार मे कड़े फेसले देश मे नजीर साबित हो रहे है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नही बचा है इसलिए विपक्ष आमजन को भ्रमित करने का काम कर रहा है जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है। आज विपक्ष निराश व हताश है क्योकि प्रदेश की देवतुल्य जनता जानती है कि भाजपा ही विकास कर सकती है। विपक्ष के पास विकास का कोई मॉडल नही है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि जनता की उम्मीदों और उनसे किए वायदों पर हमारी सरकार खरी उतरी है। आज भाजपा का कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच रहकर जनसेवा करता है, इसके लिए उन्होने भाजपा कार्यकर्ताओ को साधुवाद दिया है। डॉ. नरेश बंसल ने कहा की भाजपा सरकार ने पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा व देवभूमी की सनातन विचार को आगे रखते हुए कार्य किए है।

मुख्यमंत्री जी का संकल्प है प्रदेश की डेमोग्राफी नही बदले देंगे इस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जनभावनाओ को ध्यान मे रखते हुए यू.सी.सी. व भू-कानून लाया गया है। सख्त धर्मांतरण एवं दंगारोधी कानून बनाकर और अवैध धार्मिक स्थलों एवं शिक्षण संस्थानों पर कार्यवाही करके लैंड और लव जिहाद की देशव्यापी साजिशों पर हमने देवभूमि में पूर्ण विराम लगाने का काम किया है।

उन्होंने कहा, इन 3 वर्षों में सरकार की

अनगिनत उपलब्धियां रही हैं जिन्होंने आम लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। हमारी ही सरकार ने मातृ शक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 और सहकारी समितियों में 33 फीसदी आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण का प्रयास किया है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। श्रद्धेय अटल जी ने दिया था आज मोदी जी उत्तराखंड को सवांरने का काम कर रहे है। आज ऑल वेदर रोड समेत एन एच, स्टेट हाइवे और पीएमजीएसवाई जैसे कार्यक्रमों से राज्य में सड़कों का जाल बिछ गया है। पहाड़ पर रेल नेटवर्क अंतिम चरण में है, हवाई कनेक्टिविटी से सभी शहर जोड़े गए हैं, और अब तो रोपवे की तकनीक से भगवान और भक्त सभी दूरी कम करने पर काम हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी, नीति आयोग भी राज्य के विकास आंकड़ों पर मुहर लगा रहा है, 3 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए है व 80000 करोड़ की ग्राउंडींग हो चुकी है, चार धाम यात्रा का आंकड़ा लाखों से करोड़ों की और तेजी से बढ़ रहा है, बारों महीने चार धाम यात्रा संभव हुई है। हर घर जल व नल एवं बिजली पहुंची है। आज सोलर योजना से उत्तराखंड आत्मनिर्भर हो रहा है। कठोरतम नकल कानून लाया गया है व रिकॉर्ड 20 हजार से अधिक नौकरियां दी गई है। आयुष्मान योजना से आम लोगों के सेहत की चिंता नही है, जन औषधि केंद्र से दवा सस्ती मिल रही है, एम्स ऋषिकेश राज्य के स्वास्थ्य सेवा मे मिल का पत्थर साबित हुआ है। सरकार फ्री राशन दे रही है, उज्वला योजना, आवास योजना से आमजन का जीवन आसान हुआ है। भाजपा सरकार मे राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है।

गोपेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया भ्रमण

23 मार्च 2025 को श्री सुबोध उनियाल जी, मा. कैबिनेट मंत्री, वन, भाषा, निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा गोपेश्वर दौरे के मध्य वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान, गोपेश्वर में भ्रमण किया गया और संस्थान में छात्र-छात्राओं हेतु उपलब्ध शैक्षिक व तकनीकी आधार भूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मा. मंत्री जी ने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की समस्याओं को सुना और विश्वविद्यालय को शीघ्र ही हल निकालने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. अमित अग्रवाल ने मा. मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। मा. मंत्री जी द्वारा संस्थान के भवनों, कक्षाओं, सभागार, शोध प्रयोगशाला, पुस्कालय, कंप्यूटर लैब, इंजीनियरिंग की भिविन्न अन्य प्रयोगशालाओ का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने यू.कॉस्ट से प्रायोजित मानव-वन्य जीव संघर्ष पर संस्थान स्तर बनाये गए प्रोजेक्ट का आंकलन भी किया। संस्थान में लगभग 10 वर्षो से कार्यरत शिक्षकों ने विश्वविद्यालय द्वारा अल्पकालिक अवधि पर रखे गए शिक्षकों के अनुरूप वेतन में एकरूपता रखने हेतु ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक, बद्रीनाथ विधानसभा श्री राजेन्द्र भंडारी, बी.जे.पी. जिला अध्यक्ष श्री गजेन्द्र बर्थवाल, नगरपालिका अध्यक्ष श्री संदीप रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री नन्दन सिंह बिष्ट एवं संस्थान के शिक्षक श्री अरुण नेगी, डॉ. अरुण उनियाल, श्री अभिषेक अग्रवाल, श्री ओमबीर सैनी, श्री अरविंद कुमार, श्री हेमंत सिंह चौहान, श्री सूरज सिंह, श्रीमति मीनू खनका और संस्थान के सभी कर्मचारी व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप की ट्राफी का भव्य अनावरण

हरिद्वार के वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप की ट्राफी का अनावरण मुख्य अतिथि भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव राजीव मेहता द्वारा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डी.के. सिंह, उत्तराखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव चेतन जोशी आदि की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।

युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप की शुरुआत कबड्डी के खेल को एक नया आयाम देने तथा युवा कबड्डी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा सामने लाने के एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका वर्तमान संस्करण 6 मार्च 2025 से हरिद्वार के वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।

इस चैंपियनशिप में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। लगभग एक महीने चलने वाली इस प्रतियोगिता में पलानी टस्कर्स, सोनीपत स्पार्टन्स, कुरुक्षेत्र वॉरियर्स, यूपी फाल्कन्स, चंडीगढ़ चार्जर्स तथा वास्को वाइपर्स के साथ ही 6 अन्य टीमें 4 अप्रैल को होने वाले ग्रैंड फिनाले में विजेता ट्राफी के लिए दमखम आज़मा रही हैं।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजीव मेहता ने प्रतियोगिता के प्रारूप और आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा बेहतरीन रूप से इसके क्रियान्वयन पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह प्रतियोगिता न केवल युवा कबड्डी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहयोगी होगी बल्कि इससे प्रदेश के संघों और खिलाड़ियों को भी प्रेरणा और अनुभव मिलेगा। राजीव मेहता ने खिलाड़ियों और आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में इस तरह के और अधिक आयोजनों द्वारा वे खेल के विकास में योगदान देते रहेंगे। उत्तराखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष महेश जोशी ने अब तक के मुकाबलों में हुए रोमांचक प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कबड्डी का खेल अब एक नए रूप में निखरकर सामने आ रहा है तथा प्रदेश सरकार की खेल नीति ने इसमें कैरियर बनाने के जो भरपूर अवसर उपलब्ध कराए हैं उससे इस खेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजीव मेहता के साथ ही उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डी.के. सिंह, उत्तराखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष महेश जोशी, महासचिव चेतन जोशी, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरंग, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चन्द्र पांडे, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्वाण मुखर्जी कृपाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, कबड्डी संघ के पदाधिकारी नरेंद्र रौथाण, लीलानंद राणा, मनोज नेगी, सतीश बलूनी, नीतिन कुमार, मनीष कुमार, दिनेश कैंतुरा, ऋषिपाल सिंह, गुरूशरण सिंह, रंजना शर्मा आदि के साथ ही बड़ी संख्या में खेलप्रेमी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

भारतीय नौसेना ने किया दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता को सम्मानित

संदीप गुप्ता ने अपने संबोधन में किया अग्निवीरों को मोटीवेट

डीडीए डायमंड्स भी बने अग्निवीर पीओपी का हिस्सा

आईएनएस चिल्का, उड़ीसा यह वही ट्रेनिंग स्थान है जहां से 35 वर्ष पूर्व दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता ने भारतीय नौसेना में नौसैनिक के रूप में कॅरियर की शुरुआत की थी। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर 02/2024 बैच की पासिंग आउट परेड में संदीप गुप्ता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर संदीप गुप्ता ने सभी नौसैनिको, अग्निवीरों व स्टाफ को अपने संबोधन से मोटीवेट किया।

वहीं अग्निवीर 02/2024 बैच की पासिंग आउट परेड में कई DDA डायमंड्स शामिल थे। बता दें की 20 वर्षों में 13 हजार से ज्यादा डीडीए डायमंड्स इंडियन आर्म्ड फोर्स व मर्चेंट नेवी में अपनी सेवा दे रहे हैं। आईएनएस चिल्का ओडिसा से 402 महिला अग्निवीरों, 288 एसएसआर (मेडिकल असिस्टेंट) और 227 नाविकों सहित 2966 प्रशिक्षुओं के पास आउट होने से भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। पासिंग आउट परेड (POP) ने एक अनूठे सूर्यास्त के बाद के समारोह में 16 सप्ताह के कठोर प्रारंभिक नौसेना प्रशिक्षण के समापन को चिह्नित किया।

परेड की समीक्षा वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास, "लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने की। कमोडोर बी दीपक अनील, कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस चिल्का संचालन अधिकारी थे। पीओपी के साक्षी उच्च उपलब्धि वाले दिग्गज, जैसे दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता (सबमेरिनर), सुरेढी शिव कुमार, पूर्व एसपीओ, पूर्व पीओईएलपी, लोहरी बेसि, पूर्व पीओईएलपी, जीएस कोचर, पूर्व ईएमआर बने। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने मेधावी अग्निवीरों को पदक और ट्रॉफी प्रदान की।

देवराज सिंह राठौर, एवीआर (एमआर) और प्रमोद सिंह, एवीआर (एसएसआर) को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर एमआर और एसएसआर के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी और स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मोहित कुमार, एनवीके (जीडी) को महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक रोलिंग ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ एनवीके (जीडी) के लिए महानिदेशक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इससे पहले समापन समारोह के दौरान, एफओसीइनसी, दक्षिण कमांड ने ओवरऑल चौम्पियनशिप ट्रॉफी प्रदान की।

पहरेदारी नहीं, प्रहार करने आए 'फौजी' इमरान हाशमी, 'ग्राउंड जीरो' का दमदार टीजर आउट

इमरान हाशमी की आगामी फिल्म ग्राउंड जीरो का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टाइगर 3 के बाद से ही अभिनेता को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस बेताब थे। यूं तो इमरान स्टारर ग्राउंड जीरो की अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी लेकिन आज फिल्म का धांसू टीजर रिलीज किया गया है।

इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में ग्राउंड जीरो भी शुमार है। लंबे समय से उनकी आगामी फिल्म का इंतजार हो रहा है और आखिरकार आज उनकी फिल्म का ऑफिशियल टीजर जारी किया गया है जो एक्शन से भरा हुआ है।

टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका निभाने के बाद अब इमरान हाशमी बड़े पर्दे पर एक रियल लाइफ हीरो बनकर धमाल मचाएंगे। वह एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में दुश्मनों को धूल चटाने वाले हैं। टीजर में उनके साहस और बलिदान की झलक दिखाई गई है।

ग्राउंड जीरो का धांसू टीजर

28 मार्च 2025 को रिलीज हुआ ग्राउंड जीरो के टीजर की शुरुआत कश्मीर के अशांत माहौल से होती है, जहां दिन दहाड़े और सरेआम एक आर्मी ऑफिसर को गोली से भून दिया गया। कहानी 2001 की जहां 70 सोल्जर्स को मार दिया गया। एक रिकॉर्डेड वॉइस में आतंकवादी कहता है, 'हिंदुस्तान के वजीर-ए-आलम सुन लें... कश्मीर की आजादी, एक ही मकसद। मोहम्मद इंसाफ करेगा।'

क्या सच्ची है ग्राउंड जीरो की कहानी?

पिछले 50 सालों में BSF के सबसे जबरदस्त ऑपरेशनों में से एक से इंस्पायर्ड ग्राउंड जीरो में इमरान हाशमी BSF डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र नाथ दुबे का किरदार निभाएंगे। फिल्म में वो दो साल तक चली एक हाई-प्रोफाइल नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन को लीड करते नजर आएंगे। वह पहली बार आर्मी ऑफिसर की भूमिका में दिखाई देंगे।

ग्राउंड जीरो की स्टार कास्ट

तेजस देओस्कर के निर्देशन में बनी ग्राउंड जीरो में इमरान हाशमी के अलावा अहम भूमिका में साई ताम्हणाकर, जोया हुसैन, मुकेश तिवारी, दीपक परमेश, ललित प्रभाकर, रॉकी रैना और राहुल वोहरा जैसे कलाकार होंगे। तेजस देओस्कर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कासिम जगमगिया, विशाल रामचंदानी, संदीप सी सिधवानी, अर्हान बगाती, टैलिसमैन फिल्म्स, अभिषेक कुमार और निशिकांत रॉय ने को-प्रोडयूस किया है। इमरान हासमी की फिल्म सिनेमाघरों में 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

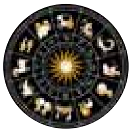
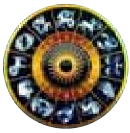

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी। अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे। धार्मिक यात्रा संबंधी पारिवारिक प्रोग्राम भी बन सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त भी रह सकती है।

वृषभ राशि– पुरानी समस्या दूर होगी। सुकून और मौज मस्ती में समय बीतेगा। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श भी होगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान रखें कि आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है। जिससे नुकसान होने की आशंका है और आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी।

मिथुन राशि– आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। भरपूर प्रयास करें और मित्रों तथा परिजनों की ओर से चल रही किसी चिंता का भी समाधान मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। किसी भी विशेष मुद्दे पर बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा छोटी सी बात पर वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है।

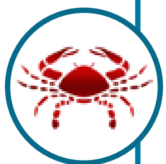

कर्क राशि– इस समय ग्रह स्थिति और भाग्य पूर्णता बेहतरीन परिस्थितियां बना रहे हैं। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे, वह अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा। कोई मूल्यवान वस्तु का सौदा करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी से सलाह-मशविरा अवश्य करें।

सिंह राशि– किसी नजदीकी मित्र की कार्यप्रणाली में भी आपका योगदान रहेगा। नया काम सीखने को मिलेगा। रूपए के मामले में किसी पर भी आंख बंदकर विश्वास न करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित अप्रिय सूचना मिलने से मन दुखी रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन न आने दें। किसी भी योजना में या उधारी देने में अपना पैसा बर्बाद न करें।

कन्या राशि– प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी-बिक्री संबंधी काम अटका हुआ है तो पूरा हो सकता है। इस समय निवेश संबंधी कामों पर पूरा ध्यान दें। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। दिन के बीच में ग्रह स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। इस समय कोई भविष्य संबंधी योजना निष्फल हो सकती हैं। तनाव लेने की बजाय दोबारा कोशिश करें। इधर-उधर की बातें करने से बचें।

तुला राशि– सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। अधिक वर्कलोड अपने ऊपर लेना तनाव और थकान का कारण बनेगा, इसलिए बीच-बीच में उचित आराम करते रहें। किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना उचित है। क्योंकि इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम हासिल होने की संभावना नहीं है।

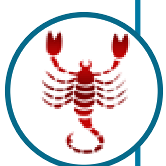

वृश्चिक राशि– किसी खास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे तो आज सफलता मिल सकती है। सुख-सुविधा संबंधी सामान की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। आपका सहज स्वभाव समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलुओं पर सोच-विचार करके योजना बनाएं।

धनु राशि– बीती हुई नकारात्मक बातों को भूलकर नए तरीके से दिनचर्या की शुरुआत करें। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ना तथा सहयोग करना आपको अतिरिक्त खुशी प्रदान करेगा। भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर में किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। किसी बनते हुए काम में रुकावट आने से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है।

मकर राशि– भूमि या किसी पॉलिसी में पैसा लगाने की योजना है, तो दिन बहुत अनुकूल है। नजदीकी संबंधी के साथ महत्वपूर्ण बातों पर विचार-विमर्श हो सकता है। जिसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। त्योहार को लेकर शॉपिंग भी रहेगी। मशीनरी या अथवा लोहे से संबंधित उपकरणों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 3

कुंभ राशि– सामाजिक तथा समिति संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान देने से आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से नई जानकारियां मिलेंगी। आप भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों में उचित सामंजस्य रहेगा। सोच-विचार करके ही कोई निर्णय लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं।

मीन राशि– कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लें तो उस पर टीके रहें। निश्चित फायदा होगा। घर में अनुशासन और उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दें।